निर्धनों की संख्या के विषय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) का सूत्र

2540. **श्री राम जेठमलानी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान यू०एन०डी०पी० द्वारा वर्ष 1996 हेतु प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धनता के स्तर की माप करने के लिए "यू०एन०डी०पी०" द्वारा नये दिशा-निर्देश बनाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सूत्र का ब्यौरा क्या है तथा इस सूत्र के अनुसार देश में निर्धनों का अनुमानित प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में निर्धनों के संबंध में अपने भी अनुमान लगाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में निर्धनों की कितनी संख्या हो जाने का सरकार का अनुमान है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 1996 में मानव वंचित के बहु आयामीय उपाय प्रारम्भ किये गए हैं जिन्हें "सामर्थ्य गरीबी उपाय" (सी पी एम) कहा जाता है। इस सूची में तीन संकेतक सम्मिलित हैं, अर्थात् (क) सु-पोषित और स्वस्थ होने का सामर्थ्य, (ख) स्वास्थ्य पुनर्निर्माण के लिए सामर्थ्य तथा (ग) शिक्षित और सुविज्ञ होने का सामर्थ्य।

(ग) सूची निम्नलिखित का सामान्य औसत है: (क) पांच साल की उम्र के बच्चों का अनुपात जो कम वजन वाले हों (ख) प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपेक्षित जन्म-दर का अनुपात (ग) 15 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं में नारी निरक्षरता का अनुपात। यू०एन०डी०पी० द्वारा वर्ष 1993 के लिए भारत में सी पी एम का अनुमान 61.5 प्रतिशत लगाया गया है। फिर भी, इसका अर्थ यह नहीं है कि 61.5 प्रतिशत आबादी गरीब है। सी पी एम प्रणाली द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कोई बना-बनाया तरीका उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा आयोजित पंचवर्षीय सर्वेक्षण आंकड़े के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। पूर्ण सर्वेक्षण परिणाम पर आधारित गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध है। यह गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे 25.5 प्रतिशत आबादी को दर्शाता है। पूर्ण सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित परवर्ती वर्षों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

Gas-Based Power Projects

2541. **SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of gas-based power projects generating power;

(b) what is the generation of power by them in M.Ws;

(c) the number of new gas-based projects sanctioned during the last five years and of what capacity;

(d) whether Government intend to import gas from Oman and if so, by when;

(e) what is the amount of gas to be imported according to the MOU signed and what would be its expected cost;

(f) whether the landfall point for the Oman gas has been finalised; if so, the location identified for the purpose; and

(g) by when the MOU would be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) There are 21 number of gas based power projects with an installed capacity of 5478 MW. The energy generation during 1996-97 upto July, 1996 was 9053 million units.

(c) Details of Gas based projects sanctioned during the last five years are as follows:

Sl. No.	Name of Project	State/Orgn.	Date of sanction	Capacity	Remarks
1.	Karaikal CCGT	Pondicherry/ P.D.C.	2/91	GT:3×5 +ST:1×7.5	Commng. in IX Plan
2.	Amguri CCGT	Assam/ASEB	8/91	*GT:8×30 +ST:4×30	**
3.	Trombay CCGT	Mah/TEC	10/91	GT:1×120 +ST:1×60	Commissioned
4.	Gandhar CCGT	Guj/NTPC	2/92	GT:3×131.7 +ST:1×220	-do-
5.	Brahmapuram DG sets	Kerala/KSEB	9/93	DG:5×20	Expected to be commd. by 96-97.
6.	Rokhia Ph-III	Tripura	3/93	GT:2×8	Commnd.
7.	Ramgarh GT-2	Raj/RSEB	5/93	35.5	Commnd.
8.	Jegurupadu CCGT	A.P./GVK IND	11/93 (CEA cleared)	GT:3×50 +ST:1×85	GT-1 Commnd. GT-2&3 Expected by 10/96 & 12/96 respectively. ST by 4/97.
9.	Godavari CCGT	A.P./Spectrum Power Ltd.	12/93 (CEA cleared)	GT:3×47 +ST:1×67	Expected to be Commnd. by 96-97.
10.	Rokhia Ph-II	Tripura	8/94	GT:2×8	Expected to be commnd. by 96-97.
11.	Agartala GT	Assam/ NEEFCO	12/94	4×21	-do-
12.	Kayamkulam	Kerala/NTPC	8/95	GT:2×130 ST:1×140	**
13.	Hazira CCGT	Gujarat/ ESSAR Power Ltd.	8/95 (CEA cleared)	GT:3×110 +ST:1×185	GTs commnd. ST-Expected to be commnd. by 11/96.
14.	Kozhikode DG sets	Kerala/ KSEB	10/95	DG:6×20	**

*Based on availability of gas; the project capacity estimated to be 280 MW
**Order for main plant equipment is yet to be placed.

(d) to (g) Later an Agreement on principal terms signed with Oman in September, 1994. Oman will design, construct, finance, own and operate a deep-sea pipeline system to transport 56.6 MMSCMD of natural gas to India.

The start-up date for the first pipeline to carry 28.3 MMSCMD will be July 1, 1999. The second line will be completed 18-24 months thereafter. The landfall point for the gas will be at Ropar Garhwali in Gujarat. The price of the imported gas is not yet fully negotiated.

Under the Agreement the detailed feasibility study for the project was to be completed by July, 1995. The study is, however, yet to be completed. Delays are expected in the start-up date mentioned above.

Development of Solar Energy in Andhra Pradesh

2542. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to launch an accelerated solar energy development programme in Andhra Pradesh in 1996-97;

(b) whether it is a fact that Andhra Pradesh is lagging behind the other States in the use and production of solar energy; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to enhance solar energy programme in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) The Government has been implementing the solar energy programme all over the country, including in the State of Andhra Pradesh. Under the programme installation of various solar photovoltaic and solar thermal devices and systems is promoted. In Andhra Pradesh, 5963 solar lanterns, 2932 street lighting systems, 780 domestic lighting systems and 4 small SPV power plants, 9652 solar cookers, and solar water heating and desalination systems of aggregate 7500 sq. m. collector area have been installed as on 31.03.1996. The State is not lagging behind in the implementation of solar enrgy programme. During 1996-97, it is proposed to distribute 5000 solar lanterns, and instal 500 solar home lighting systems and 100 solar street lighting systems in the State.

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किये गए निवेश का मूल्यांकन

2543. **श्री राघव जी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए निवेश का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उत्पादित खाद्य तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात की काफी संभावना है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (घ) मंत्रालय मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए स्वयं कोई मूल्यांकन नहीं करता लेकिन वह अपनी योजना स्कीमों के तहत ऐसे अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकारों, संस्थाओं और संगठनों को सहायता उपलब्ध कराता है। मध्य प्रदेश सरकार/वहां के किसी संगठन से ऐसे अध्ययन करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ फल तथा सब्जी उत्पाद, सोया आधारित उत्पाद, स्नैक फूड, मांस तथा पाल्ट्री उत्पाद आदि शामिल हैं।

मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतियों को उदार बनाया है और अल्कोहल पेयों के विण्वन और